रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर ₹3,300 टन की सब्सिडी बहाल

[जयश्री भोसले | पुणे]

पिछली सरकार के फैसले को पलटते हुए मोदी सरकार ने रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर 3,300 रुपये प्रति टन की सब्सिडी बहाल कर दी है। यह सब्सिडी जून और जुलाई के लिए दी गई है। सरकार ने बुधवार रात को नोटिफिकेशन जारी करके यह सब्सिडी बहाल की। महाराष्ट्र में अगले चार महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इसके जरिये वहां के गन्ना किसानों को खुश करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार का यह कदम उत्तर प्रदेश में भी उसकी सियासत मजबूत कर सकता है, जहां पार्टी को लोकसभा चुनाव में शानदार जीत मिली थी। बीजेपी यहां अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है।

पिछली सरकार ने सब्सिडी घटाकर 2,277 रुपये टन कर दी थी और उसकी योजना स्कीम को सितंबर में बंद करने की थी। शुगर सीजन अक्टूबर से लेकर सितंबर तक चलता है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाइज ने 11 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सब्सिडी की रकम 3,300 रुपये प्रति टन रखी गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह छूट जून और जुलाई महीने के लिए है। इससे पहले 5 जून को फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने मंत्रियों के समूह के साथ मीटिंग की थी। इसमें नितिन गडकरी, मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, कलराज मिश्रा सहित कुछ और मंत्री शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि फूड मिनिस्टर ने इस स्कीम को जारी रखने की सहमति दी है जबकि यूपीए के फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने इसे बंद करने का फैसला लिया था। यूपीए सरकार ने डोमेस्टिक शुगर इंडस्ट्री की मदद के लिए कच्ची चीनी के निर्यात पर सब्सिडी देने की मंजूरी दी थी। दरअसल, शुगर मिलों पर किसानों का काफी पैसा बकाया था। इंडस्ट्री इसे चुकाने के लिए यूपीए सरकार से रियायत की मांग कर रही थी। उस वक्त चीनी का स्टॉक ज्यादा होने के चलते डोमेस्टिक मार्केट में इसकी कीमत भी कम बनी हुई थी। यूपीए सरकार ने फरवरी और मार्च के लिए मिलों को रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर 3,300 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी थी। उसके बाद इस बारे में हर दो महीने में फैसला किया जाना था।

> **महाराष्ट्र में** अगले चार महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी इसके जरिये वहां के गन्ना किसानों को खुश करने की कोशिश कर रही है

सब्सिडी की रकम के बारे में डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू देखकर बदलाव करने का फैसला हुआ था। शुरुआती योजना के मुताबिक स्कीम को अगस्त-सितंबर तक जारी रखने की बात थी। हालांकि स्कीम लागू होने के पहले दो महीने के बाद सरकार ने सब्सिडी रेट को सिर्फ मई में बदलाव। तब उसने इसमें 30 पर्सेंट से ज्यादा की कटौती की थी। हालांकि केंद्र में सरकार बदलने से रॉ शुगर एक्सपोर्ट इनसेंटिव स्कीम में फिर से जान लौटी है। मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने कहा कि सब्सिडी में कमी के बाद रॉ शुगर का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। अब यह एक बार फिर शुरू हो सकता है।

Economic Times
Hindi
13/6/14